(ग) क्या इस छूट से इन मार्गों पर चलने वाली रेलगाड़ियों में यात्रियों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी-कितनी?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1994-95 में तथा 01.04.95 से कालका से शिमला और पठानकोट से जोगिन्दर नगर तक दर्जा-वार किराए निम्नलिखित हैं:—

कालका से शिमला

	1994-95	01.04.95 से
	(रु॰)	(रु॰)
रेल मोटर कार	199	137
पहला दर्जा	179	114
कुर्सी यान	112	77
दूसरा दर्जा	36	14
पठान कोट से जोगिन्दर नगर:		
पहला दर्जा	219	159
दूसरा दर्जा	032	024

(ग) कालका-शिमला खण्ड पर अप्रैल 1994 के दौरान 3032 यात्रियों की तुलना में अप्रैल 1995 के दौरान 9198 यात्री बुक किए गये थे। यात्री यातायात में 203.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई पठानकोट-जोगिन्दर नगर खण्ड पर अप्रैल 1994 के दौरान 18,751 यात्रियों की तुलना में अप्रैल 1995 के दौरान 24,901 यात्री बुक किए गए यात्री यातायात में 32.8% की वृद्धि हुई।

रेलवे में सुधार हेतु समितियों की सिफारिशें

7216. श्री राम जेठमलानी:
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय परिवहन प्रणाली की समस्या की पुनरीक्षा करने हेतु यूनाइटेड नेशन्स डिपार्टमेंट फार डेवलेपमेंट एंड मैनेजमेंट सर्विसेज द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा नियुक्त कतिपय अन्य समितियों अथवा आयोगों ने भी रेलवे में सुधार हेतु सिफारिशें दी हैं;

(घ) यदि हां, तो सिफारिशें कब तक और किस-किस रूप में दी गई हैं और

(ङ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया है; यदि हां तो कौन-कौन सी सिफारिशें कब-कब क्रियान्वित की गयी हैं?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ): (क) और (ख) विकास समर्थन और प्रबंध सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र के विभाग ने भारत की राष्ट्रीय परिवहन नीति का अध्ययन किया था जिसका निष्पादन दो चरणों के जरिए अर्थात परिवहन आवश्यकता निर्धारण अभियान और भारत की राष्ट्रीय परिवहन नीति के बारे में मुख्य अध्ययन, किया जाना था। यद्यपि पहली रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, दूसरे पहलू के बारे में रिपोर्ट अभी प्राप्त की जानी है।

रेलों के संबंध में उनकी परिवहन आवश्यकता निर्धारण अभियान रिपोर्ट में की गई कुछ सिफारिशों में भारतीय रेलों की कार्यप्रणाली में व्यापारोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाना, सरकार द्वारा "सामाजिक दायित्वों" पर हानि की क्षतिपूर्ति, फालतू कर्मचारियों को पुन: तैनात करना और पुन: प्रशिक्षण देना तथा उनकी निपुणता में वृद्धि करना, रेल उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, नोडल स्थल स्थापित करके उच्च दरों वाला यातायात प्राप्त करना, कंटेनरीकृत कार्गो का विस्तार करना, बचत करने वाले मुख्य क्षेत्रों का पता लगाना, प्रबंधन तकनीकों का विस्तार, नई प्रौद्योगिकी अपनाना आदि शामिल है।

(ग) से (ङ) श्री प्रकाश टंडन की अध्यक्षता में भारतीय रेलों की संगठनात्मक अवसंरचना और प्रबंधन की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई थी और मार्च, 1994 में इस समिति की सिफारिशें दी गई थीं, समिति की सिफारिशों में आधुनिक वित्तीय सूचना प्रणालियां, उपभोक्ता की ओर ध्यान देते हुए व्यापारोन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना, निवेश योजना प्रणाली का सुधार करना, मानव संसाधन विकास और संगठनात्मक पुनर्संरचना संबंधी क्षेत्र शामिल हैं।

श्री डी॰ एफ॰ नांजुंदप्पा की अध्यक्षता में परिचालन की लागत में वृद्धि, ढोए जाने वाले यातायात की मात्रा और स्वरूप, प्रौद्योगिकी में बदलाव, राष्ट्रीय परिवहन नीति तथा देश के समग्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए किराया और मालभाड़ा संरचना की पूरी रूपरेखा और अन्य आनुषांगिक मामलों की जांच करने के लिए रेल किराया और मालभाड़ा समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिशें दिसंबर 1993 में प्राप्त हुई थीं।

ये रिपोर्टें वैचारिक स्वरूप की थीं और रिपोर्टों की जांच के बाद मंत्रालय ने विस्तृत कार्यान्वयन के मुद्दे की जांच करने हेतु निम्नलिखित समितियां/कार्य बलों का गठन किया है:

(i) हसन इकबाल समिति:

श्री हसन इकबाल रेलवे के सेवानिवृत्त वित्तायुक्त की अध्यक्षता में लागत/लाभ केन्द्रों का पता लगाने और लेखा प्रणाली का विकास करने तथा वित्तीय सूचना प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण करने के लिए। समिति ने अपनी वैचारिक रिपोर्ट दिसंबर 1994 में प्रस्तुत की है।

(ii) के॰ वी॰ गुप्ता-नारायण समिति:

उन व्यक्तियों को तैयार करने के लिए जो केवल मंडल रेल प्रबंधक, अपर महा प्रबंधक, महाप्रबंधक और सदस्य जैसी सामान्य प्रबंधन स्थितियों पर तैनात होंगे, विकास तथा प्रवरण प्रक्रिया सहित एक एकीकृत भारतीय रेलवे सेवा के सृजन के लिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट का भाग-I प्रस्तुत कर दिया है।

(iii) पौलोस समिति:

श्री ए.वी. पौलोस, रेलवे के सेवानिवृत्त वित्तायुक्त की अध्यक्षता में भारतीय रेलों की पूंजी पुनर्संरचना और यातायात में सकारात्मक फेर-बदल और लागत प्रणाली की समीक्षा के लिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट का भाग-I दिसम्बर 1994 में प्रस्तुत किया है।

दिल्ली रेलवे डिवीजन में सरकारी आवास के लिए बनी प्रतीक्षा सूची

7217. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी रिकार्ड के अनुसार कितने रेल कर्मचारियों ने सरकारी आवास के लिए श्रेणी-वार दिल्ली में भवन अधीक्षक (आवास) दिल्ली डिवीजन विभाग, रेलवे के पास 30 अप्रैल 1995 तक अपना पंजीकरण करवाया था और इस संबंध में उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) किस वर्ष तक की विभिन्न श्रेणियों की प्रतीक्षा सूचियों को निपटा दिया गया है?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ):

(क) आवास की कोटि	पंजीकृत 30.4.95 को कर्मचारियों की संख्या
अनिवार्य	20,331
गैर-अनिवार्य	11,424

(ख) आवास की टाइप	कोटि	जिस तारीख तक प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई
टाइप-I	गैर-अनिवार्य	19.12.58
	अनिवार्य	15.5.91
टाइप-II	गैर-अनिवार्य	31.7.59
	अनिवार्य	21.1.84
टाइप-III	गैर-अनिवार्य	4.11.72
	अनिवार्य	17.4.85
टाइप-IV	गैर-अनिवार्य	9.4.84
	अनिवार्य	22.2.85

रेल विभाग को आवश्यक सेवा के अंतर्गत लाया जाना

7218. **श्री संघ प्रिय गौतम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अधीन किन-किन विभागों को आवश्यक सेवा के अंतर्गत रखा गया है; और

(ख) क्या सरकार ने रेल आरक्षण विभाग को भी इस सेवा के अंतर्गत शामिल किया है?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ): (क) और (ख) रेल मंत्रालय के अधीन विभागों का अनिवार्य तथा गैर अनिवार्य के रूप में कोई वर्गीकरण नहीं है, तथापि, क्वार्टरों के आवंटन के प्रयोजनार्थ कर्मचारियों को, अनिवार्य तथा गैर अनिवार्य कोटियों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश मौजूद हैं जो कि स्थानीय हालत तथा कर्मचारी के संबंधित विभाग का ध्यान किए बिना उसको रेलवे की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं।

Decrease in the demand of wagons

7219. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state.

(a) whether it is a fact that demands of wagons has decreased during the last ten years;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, the demand of wagons in the country during 1984-85 to 1994-95, year-wise?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C K. JAFFER SHARIEF); (a) and (b) The demand for wagons is need-based and is related to transported output. The reduction in demand